

झारखण्ड सरकार

विधि विभाग



सत्यमेव जयते

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन)  
विधेयक, 2022

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,  
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

विषय-सूची

प्रारंभिक

1. सक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ
2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा-27 में संशोधन



## झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणतंत्र के 73वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो: -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

- (1) यह अधिनियम 'झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022' कहलाएगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 1 की उप धारा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- (3) यह अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 27 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं -

- (1) मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ख) -  
" मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ख) में अंकित शब्द समुह ' चक्रानुक्रम में ' को विलोपित किया जाता है।"
- (2) मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ग) -  
" मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ग) में अंकित शब्द समुह ' चक्रानुक्रम में ' को विलोपित किया जाता है।"
- (3) मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (च) के स्पष्टीकरण -  
" मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (च) के स्पष्टीकरण में अंकित शब्द समुहों ' अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा ' को विलोपित किया जाता है।"

## उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-27 (2) में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों के लिए चक्रानुक्रम सिद्धान्त संबंधी प्रावधान के आधार पर महापौर/अध्यक्ष पद का आरक्षण के पश्चात विभिन्न स्थानीय नगर निकायों में उन आरक्षित पदों के आवंटन में विसंगति उत्पन्न हो रही है।

भारतीय संविधान की धारा-243(T)(4) में महापौर/अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के सीटों को आरक्षित किये जाने के लिए विधि बनाने हेतु राज्य विधान मंडल को शक्ति प्रदान की गई है।

अतएव, उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में महापौर/अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों के आवंटन के निमित्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-27 (2) में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

तदनुसार उपरोक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रख्यापित करना इस विधेयक का अभीष्ट है।

(हेमन्त सोरेन)  
भार साधक-सदस्य